



प्रवास पर जीवन का समर्थन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-॥
(सामाजिक न्याय) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- अरुण कुमार, एम. सुरेश बाबू (प्रोफेसर,
आईआईटी, मद्रास)

1 नवम्बर, 2018

‘नागरिकों को बेहतर कमाई और गरीबी की समस्या से निजात दिलाने एवं उन्हें सक्षम बनाने के लिए वर्तमान में आंतरिक प्रवासन की राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।’

हालांकि प्रवास, खपत में वृद्धि होने और मूल रूप से पूर्ण गरीबी से परिवारों को बाहर निकालने में मदद करती है, फिर भी यह संकट से मुक्त नहीं है, अर्थात् बेरोजगारी या कृषि में अल्प रोजगार, प्राकृतिक आपदाएं और इनपुट / आउटपुट बाजार की खामियों में बेरोजगारी के कारण परेशानी।

आंतरिक प्रवासन पुश और / या पुल कारकों द्वारा संचालित किया जा सकता है। भारत में, हाल के दशकों में, कृषि संकट (जो एक पुश कारक है) और शहरी क्षेत्रों (जो एक पुल कारक) में बेहतर भुगतान रोजगार में वृद्धि आंतरिक प्रवासन के चालक रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, कम संघर्ष वाले क्षेत्रों में प्रवासन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक रोजगार की मांग है।

प्रवास की लागत

हालांकि, गंतव्य पर एक प्रवासी में कौशल की कमी श्रम बाजार में प्रवेश करने में एक बड़ी बाधा साबित होती है। इसके अलावा, आधुनिक औपचारिक शहरी क्षेत्र अक्सर शहरी श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले ग्रामीण श्रमिकों की बड़ी संख्या को शामिल करने में सक्षम नहीं होते हैं।

इसने शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास को जन्म दिया है, जो उच्च गरीबी और कमजोरियों द्वारा चिह्नित है। शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को भारत जैसे देशों में एक क्षणिक घटना के रूप में गलत तरीके से समझा जाता है। वास्तव में, इसका विस्तार वर्षों से होता आ रहा है और यह शहरी रोजगार के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार भी है।

शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में अधिकांश रोजगार में कम भुगतान किया जाता है और स्व-नियोजित श्रमिकों को शामिल करती हैं। फिर भेदभाव के विभिन्न रूप सामने आते हैं जो प्रवासियों को बेहतर भुगतान वाली रोजगार से दूर रखते हैं।

वर्ष 2014 के आंकड़ों के मुताबिक प्रवासी श्रमिक, गैर-प्रवासी श्रमिकों द्वारा कमाए गये धन का केवल दो-तिहाई ही कमा पाते हैं। इसके अलावा, इन्हें प्रवास के कारण एक बड़ी लागत चुकानी पड़ती है जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी होने की भी संभावना बढ़ जाती है।

अक्सर ये लागत बढ़ जाती है, क्योंकि वे राज्य द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रणाली से वंचित रह जाते हैं। जिसके कारण वे इन खर्चों को पूरा करने के लिए नियोक्ताओं से उधार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस तरह से ली गयी लगातार उधार उन्हें अपने ऋण की चुकौती के लिए संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करता है।

शहरी अनौपचारिक श्रम बाजार के भीतर भी, व्यवसाय, उद्योग (श्रम-बाजार विभाजन) द्वारा श्रम बाजार का विभाजन, प्रवासियों को निचले सिरे तक सीमित करता है। अक्सर, इस तरह के विभाजन सामाजिक पहचान में मतभेदों को मजबूत करता है, जिसके बाद भेदभाव के नए-नए रूप सामने आने लगते हैं।

प्रवासन के लाभ

इन मुद्दों के बावजूद, आंतरिक प्रवासन के कारण परिवारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, खासकर उच्च कौशल, सामाजिक जुड़ाव और संपत्ति वाले लोगों के लिए। निचली जातियों और जनजातियों से संबंधित प्रवासियों ने ग्रामीण इलाकों में अपने घरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और गरीबी से बाहर निकलने में अच्छा सुधार किया है।

आंकड़ों के अनुसार निचली जातियों और जनजातियों के बीच घरेलू आय का अनुपात उच्च हो गया है, जो परिवार के सदस्यों की ऋण लेने की योग्यता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे वे ऋण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

अल्पकालिक प्रवासियों को लक्षित करने वाले हस्तक्षेपों को भी इस तथ्य की पहचानने की आवश्यकता है कि शहरी क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रवास और ग्रामीण आजीविका में सुधार करने में इसकी भूमिका परिवारों की लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति का एक सतत हिस्सा है। गैर सरकारी संगठनों और निजी उद्यमियों द्वारा स्थानीय हस्तक्षेपों को भी प्रवासियों को लक्षित करते समय जाति पदानुक्रमों और सामाजिक परिणामों से मजबूत सांस्कृतिक आयामों पर विचार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नीति क्यों?

आंतरिक प्रवासन की दिशा में राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता इस तथ्य से संबंधित है कि 20% से कम शहरी प्रवासियों के पास पहले से सुनिश्चित किया जा चुका रोजगार था और लगभग दो-तिहाई लोगों ने शहर में प्रवेश करने के एक सप्ताह के भीतर ही रोजगार खोजने में कामयाब हो गये थे, जिसे 90 के दशक में किये गये एक अध्ययन में दर्शाया गया है और हमने वर्ष 2015 में तमिलनाडु में क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से इसे सत्यापित भी किया है।



एक पहले से सुनिश्चित रोजगार के कारण शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है जिससे शहरी क्षेत्र में जाने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। सामाजिक नेटवर्क के साथ प्रवास करने से पहले रोजगार उपलब्धता पर जानकारी तक पहुंच बेरोजगारी की अवधि को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्रोत क्षेत्र में सोशल नेटवर्क्स प्रवासियों को न केवल रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक पूंजी के रूप में भी महत्वपूर्ण साबित होती हैं।

भारत में, नीतिगत हस्तक्षेपों का बड़ा हिस्सा, जिससे प्रवासियों को भी लाभ हो सकता है, मानव विकास को बढ़ाने के लिए निर्देशित हैं; जिसमें से कुछ का उद्देश्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करना है। इस मुद्दे पर नीतियाँ दोतरफा होनी चाहिए। जिसमें पहले का उद्देश्य संकट से प्रेरित प्रवास को कम करना होना चाहिए और दूसरे का उद्देश्य काम की शर्तों को, रोजगार की शर्तों को और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच को सुनिश्चित करने से संबंधित होना चाहिए।

प्रवासी-केंद्रित समाधान प्रवासियों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिससे उनकी कमाई में इजाफा होगा और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। यहाँ प्रवासियों के अस्तित्व और प्रवासियों के रोजगार के उद्देश्य से निर्मित नीतियों के बीच अंतर स्पष्ट करने की भी आवश्यकता है।

लंबी अवधि के दौरान निरंतर गतिशील समाधान एकल-बिंदु पर स्थिर समाधान की तुलना में बेहतर परिणाम देगा, खासकर मौसमी प्रवासियों के संदर्भ में। स्थानीय निकायों और एनजीओ जो स्थानीय क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन लाते हैं उन्हें अधिक से अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

प्रवासियों के उद्देश्य से निर्मित नीतियों की कमी है। उन्नत कौशल विकास के उद्देश्य से निर्मित नीति श्रम बाजार में आसान प्रवेश को सक्षम बनाएगा। हमें विशेष रूप से व्यक्तिगत और घरेलू प्रवासियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से स्वतंत्र नीतियों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि घरेलू प्रवासन को व्यक्तिगत प्रवासन से अधिक आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसे आधारभूत संरचना तक पहुंच की आवश्यकता होती है। विभिन्न नीतियों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, रोजगार से संबंधित सरकारी हस्तक्षेपों को बाजार के नेतृत्व वाले नीतियों जैसे माइक्रोफाइनेंस पहलों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिससे आय के उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद करते हैं।

GS World टीम...

प्रवासन

चर्चा में क्यों?

- भारत में प्रवास गाँवों से शहरों की ओर हो रहा है। ग्रामीण जनसंख्या शीघ्रता से शहरों की ओर भाग रही है। क्योंकि अच्छे जीवन की तलाश हर व्यक्ति करता है।
- इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को भी प्रवास की समस्या का जिम्मेदार माना जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लघु/कुटीर उद्योगों का पतन होना, कृषि की समाप्ति होना, भूमिहीन कृषक, गरीबी की समस्या, सामाजिक अयोग्यतायें, अधिक मजदूरी की इच्छा, नगरों का आकर्षण, बेरोजगारी आदि अनेक कारण अध्ययन क्षेत्र में सामने आये हैं।

क्या है?

- एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन कहलाता है।
- प्रवासन सामान्यतः दो प्रकार का होता है- स्थायी प्रवासन एवं अस्थायी प्रवासन। अस्थायी प्रवासन वार्षिक, मौसमी या दैनिक (दो शहरों के मध्य) रूप में हो सकता है।
- अपने मूल स्थान एवं गंतव्य के आधार पर प्रवासन के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं-
- ग्राम से ग्राम की ओर R→R

- ग्राम से शहर की ओर R→U
- शहर से शहर की ओर U→U
- शहर से ग्राम की ओर U→R

प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानवीय व्यवस्थित प्रवास को सुनिश्चित करती है तथा प्रवासियों को पुनर्वास अवसरों की खोज में सहायता प्रदान करती है।
- इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

भारत में प्रवासन की प्रवृत्तियाँ

- आंतरिक प्रवासन के दो प्रतिरूप अंतःराज्यीय एवं अंतरराज्यीय हो सकते हैं-
- अतःराज्यीय प्रवासन राज्य की सीमाओं के भीतर ही होता है, जबकि अंतरराज्यीय प्रवासन के संदर्भ में व्यक्ति अपने राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में बस जाते हैं।
- सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 79.78% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 68.70 तक सिमट गयी है।
- इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर है कि किस तरह जनसंख्या जा पलायन हो रहा है जिसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन भी बढ़ रहा है।

- जहाँ एक तरफ शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ गाँवों की जनसँख्या घट रही है जिसके कारण कई गाँवा विलुप्त हो गए हैं और कई विलुप्ति के कगार पर है।
- भारत सरकार द्वारा इन प्रवासों को रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे:- भारत निर्माण, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक मुश्त सहायता, सूक्ष्म एवं लघु अवधि ऋण योजना,

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग सहायता योजना आदि।

- इन सब योजनाओं का अभी तक कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता। अभी भी गाँवों से पलायन जारी है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में जो की एक चिंता का विषय है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'प्रवासन के लाभ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस संबंध में आँकड़ों के अनुसार निचली जातियों और जनजातियों के मध्य घरेलू आय का अनुपात उच्च हो गया है।
2. भारत में आंतरिक प्रवासन से सबसे अधिक लाभ मणिपुर को हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

2. सोशल नेटवर्क प्रवासियों के लिये निम्नलिखित में से किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होता है?

1. प्रवासियों को रोजगार की जानकारी प्रदान करने में
2. सामाजिक पूंजी के रूप में
3. प्रवासियों के बेरोजगारी की अवधि को कम करने में

कूट:-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'आंतरिक प्रवासन भी समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकता है परंतु आंतरिक प्रवासन के लिये राष्ट्रीय नीति इस समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को और तीव्र कर सकती है।' विश्लेषण कीजिए
(शब्द-250)

नोट :

31 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c) और 3(c) होगा।